

13.04 hrs.

Title: Introduction of the Constitution (Ninety- Seventh Amendment) Bill, 2002 (Amendment of articles 75, 164, insertion of new article 361B and amendment of the Tenth Schedule).

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India. "

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, the hon. Minister is seeking the permission of this House to introduce this Bill, and we support it. We have no objection to it.

I had the occasion to go through the Bill also. There are many salutary provisions. But we may have different views on different provisions. So, my only request at this stage is that this Bill, as all other Bills, should go to the Standing Committee.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, यब बिल जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें मैं मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि दल-बदल के लिए दलों को प्रतिबंधित किया जाए तो दल-बदल अपने आप रुक जाएगा। कोई न कोई राजनीतिक दल दल-बदल को प्रश्रय देने का काम करता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब बिल आएगा, उस समय आप इस पर बोल सकते हैं।

SHRI ARUN JAITLEY: There is absolutely no objection; hon. Member Shri Shivraj Patil has made a very valid suggestion. It is a Constitution Amendment Bill of an immense significance. It obviously cannot be taken up in this Session. The Government itself is committed to have a larger consensus on this issue. So, this may go to the Standing Committee.

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section-2, dt. 5.5.2003

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Thank you.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बिल द्वारा अधिकार का प्रयोग कर रही है लेकिन उसे कर्तव्य का भी प्रयोग करना चाहिए। जो राजनीतिक दल जिस मैनिफेस्टो पर चुनाव जीत कर आए, उसे लागू भी करे। ऐसा न हो कि आप पूर्व चल रहे हैं लेकिन पश्चिम चलना शुरू कर दें। चूंकि केन्द्र में सरकार है, पार्टी नहीं। यदि सौ प्रतिशत एमपीज किसी कानून के खिलाफ होंगे तो सरकार जो कानून बनाएगी, उन्हें वह मानना पड़ेगा। हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। यह एक खतरनाक चीज है कि जो पार्टी जिस मैनिफेस्टो पर चुनाव जीत कर आए, लेकिन उसके खिलाफ काम करें और पार्टी के दूसरे लोग जब उसका विरोध करें तो सरकार कह दे कि हमें यह करना है। ऐसे में हर राजनीतिक दल के एमपी को वोट देना पड़ेगा वरना सभी की मेम्बरशिप चली जाएगी। यह एक खतरनाक ट्रेंड है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप चर्चा के समय, इस विषय पर बोल सकते हैं।

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce the Bill.

13.07 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

4. Hrs.